



नेस्टा - वे फॉरवर्ड
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक रिपोर्ट
अप्रैल और मई 2024

विषयवस्तु

1. परिचय	2
2. मुख्य बातें	4
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा	5
4. एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल	10
4.1. परिपूर्णता स्थिति	10
4.2. सर्वोत्तम परिपाटियाँ – एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल	12
4.2.1. उत्तराखंड (ई-सेवाएं अपणि सरकार)	13
4.2.2. सिक्किम (सिंगल साइन ऑन)	14
4.2.3. आंध्र प्रदेश (एपी सेवा पोर्टल)	15
5. पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा सुपुर्दगी को सुदृढ़ करना	16
6. उन्नत ई-सेवा सुपुर्दगी के लिए डिजिटल पहल	18
6.1 सर्विस प्लस	2
6.2 उमंग	20
7. सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार	21
8. परिशिष्ट	22
8.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की स्थिति की मासिक प्रगति	22

1. परिचय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सात क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बेंचमार्किंग प्रयोग के रूप में ई-सेवाओं की सुपुर्दगी के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा सुपुर्दगी मूल्यांकन (नेस्डा) फ्रेमवर्क तैयार किया। डीएआरपीजी का आशय नेस्डा अध्ययन को द्विवार्षिक रूप से आयोजित करने का है।

नेस्डा 2021 के उत्साहजनक निष्कर्षों के मद्देनजर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, ई सेवा सुपुर्दगी में मासिक प्रगति की निगरानी के लिए नेस्डा वे फॉरवर्ड पीएमयू की स्थापना की गई। डीएआरपीजी, नेस्डा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एसपीओसी के साथ नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवा सुपुर्दगी में हुई प्रगति और एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टलों में वृद्धि की निगरानी करता है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवा सुपुर्दगी की स्थिति की निगरानी के लिए 9 नेस्डा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई हैं।

2023 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जारी की गई मासिक रिपोर्टों में विशेष रूप से सात विशेष क्षेत्रों अर्थात् पर्यटन (मई), पर्यावरण (जून), शिक्षा (जुलाई), श्रम और रोजगार (अगस्त), वित्त (सितंबर), कृषि, स्वास्थ्य और गृह सुरक्षा सहित समाज कल्याण (अक्टूबर) और स्थानीय शासन और जनोपयोगी सेवाएं (नवंबर) में से प्रत्येक में ई-सेवाओं का गहन विश्लेषण शामिल है।

आगामी मासिक का लक्ष्य ई-सेवाओं की बेहतर सुपुर्दगी के लिए राष्ट्र के प्रयासों को संस्थागत बनाना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को द्विवार्षिक नेस्डा के लिए तैयार करना है।

नेस्डा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट के वर्णित उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क. ई-सेवाओं की परिपूर्णता

- सभी अभिचिन्हित 56 अनिवार्य ई-सेवाओं का प्रावधान
- प्रदान की गई ई-सेवाओं की कुल संख्या की सुपुर्दगी में वृद्धि
- अभिचिन्हित सामान्य सेवाओं का प्रावधान

ख. फेसलैस और स्वप्रेरणा-आधारित सेवा सुपुर्दगी को बढ़ावा देना

- फेसलैस रूप में अर्थात् फिजिकल विजिट, कागजी कार्रवाई और मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी की निगरानी।
- नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उनकी पात्रता के अनुसार ई-सेवाएँ प्रदान करना

ग. एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टलों का सुदृढीकरण

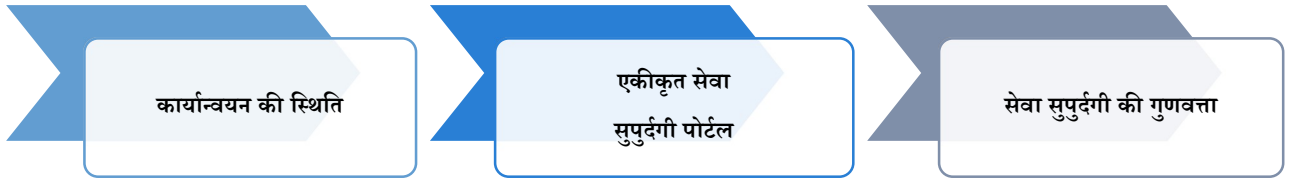
- विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल को सुदृढ करना।

- सर्विस प्लस, माईस्कीम, उमंग आदि जैसे अन्य सरकारी प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण ।

घ. बाधाओं की पहचान और सर्वोत्तम परिपाटियों का प्रसार

- मौजूदा अंतरालों का पता लगाना और नेस्टा मूल्यांकन मापदंडों के स्कोर में सुधार करना ।
- उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों से सीख ।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नेस्टा वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट, अप्रैल और मई 2024, दिनांक 03 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट पर आधारित है ।



2. मुख्य बातें

कार्यान्वयन की स्थिति

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 16,581 सेवाएं प्रदान की जाती हैं
- जम्मू और कश्मीर अधिकतम ई-सेवाएं(1140) प्रदान करता है
- अधिकतम ई-सेवाएं (5,312) – स्थानीय शासन और जनोपयोगी सेवा क्षेत्र में हैं
- 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,530 (56*36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) उपलब्ध हैं, जिससे परिपूर्णता 76% हो गई है
- हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड ने 56 अनिवार्य ई-सेवाओं में 100% परिपूर्णता हासिल कर ली है

एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल

- जम्मू और कश्मीर, केरल, असम और ओडिशा अपनी 100% सेवाएं अपने अभिचिन्हित एकल एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल यानी, क्रमशः ई-उन्नत (1140), ई-सेवानम (911), सेवा सेतु (461) और ओडिशा वन (404) के माध्यम से प्रदान करते हैं।
- उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया अपणि सरकार पोर्टल, निर्बाध रूप से नागरिक-अभिमुख सेवाएं प्रदान करता है।
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया एपी सेवा पोर्टल निवासियों को सीधे तौर पर वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विस प्रदान करता है।
- सिक्किम सरकार द्वारा बनाया गया सिक्किम जीओ पोर्टल, सिंगल साइन-ऑन प्रणाली के साथ ऐक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस को सुव्यवस्थित करता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा सुपुर्दगी को सुदृढ़ करना

- राज्य में ई-सेवा सुपुर्दगी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए 29 मई, 2024 को त्रिपुरा सरकार के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

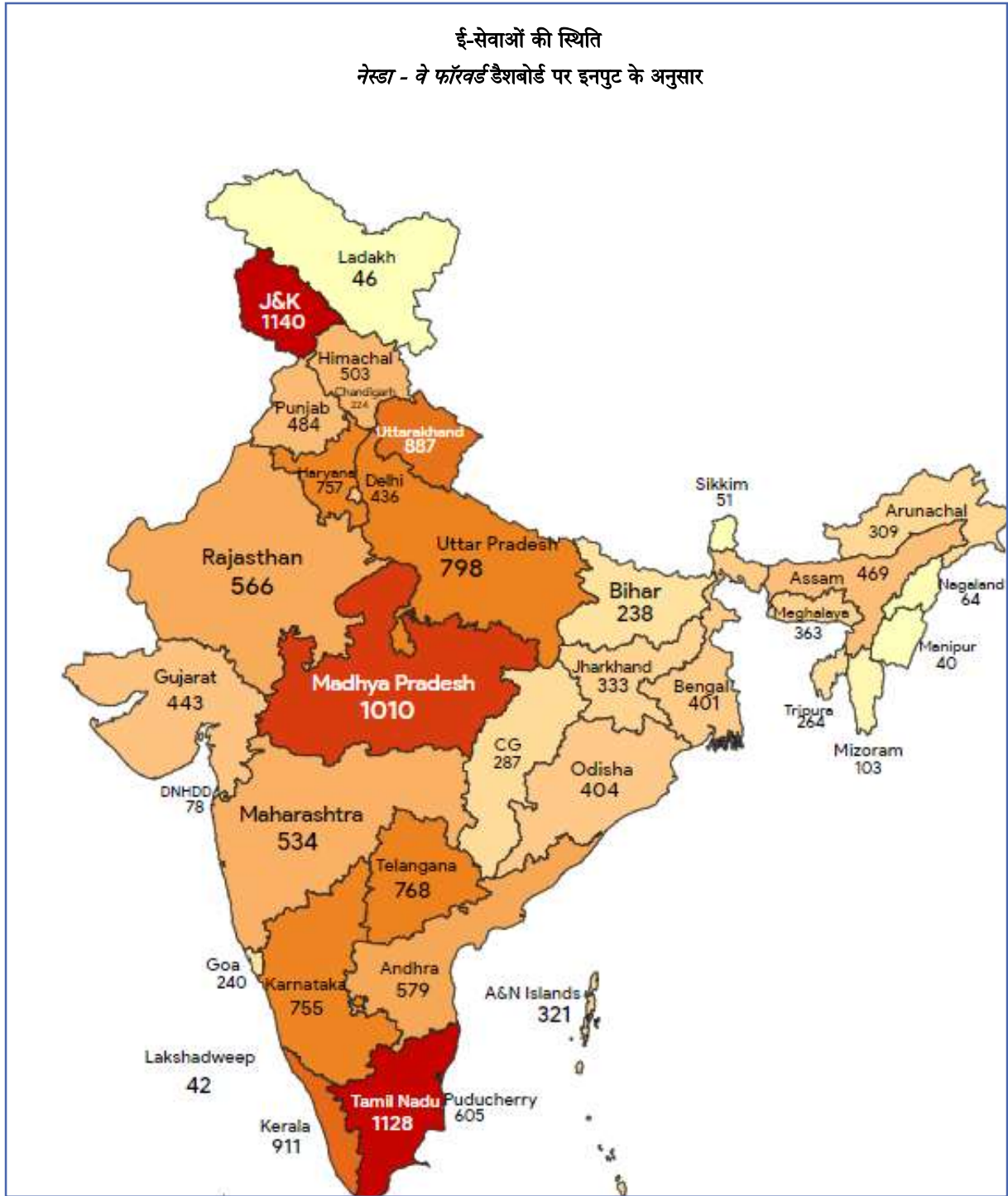
सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार

- तीन नए मूल्यांकन मापदंडों जैसे ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-भागीदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के तहत हुई प्रगति की निगरानी के लिए नेस्टा वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर नए प्रगतिशील पैरामीटर टैब शुरू किए गए हैं।



3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा

ई-सेवाओं की स्थिति
नेस्डा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



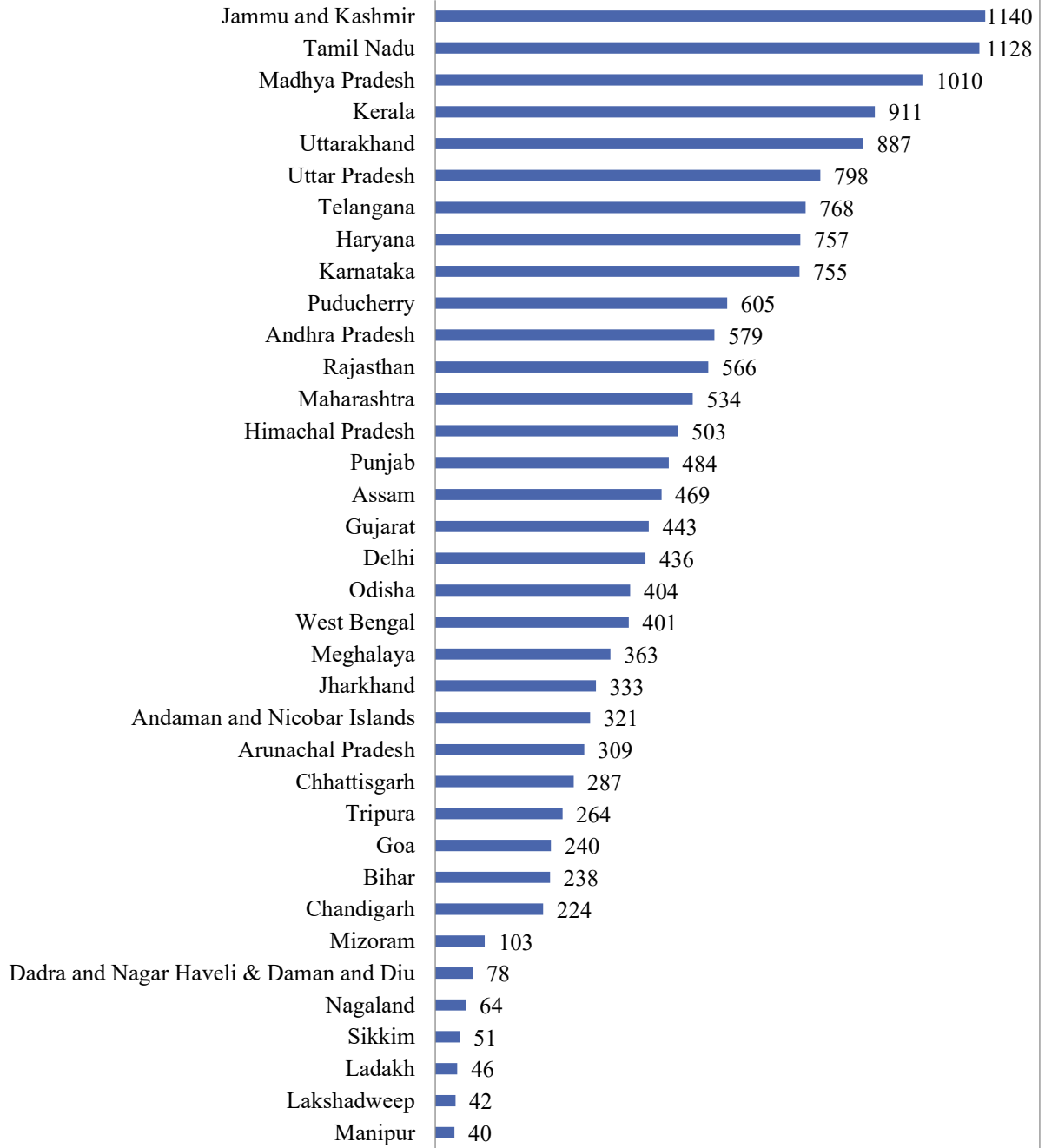
कुल ई-सेवाएं
16,581

नोट: उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 03/06/2024 तक अपलोड किए गए हैं।



ई-सेवाओं की स्थिति

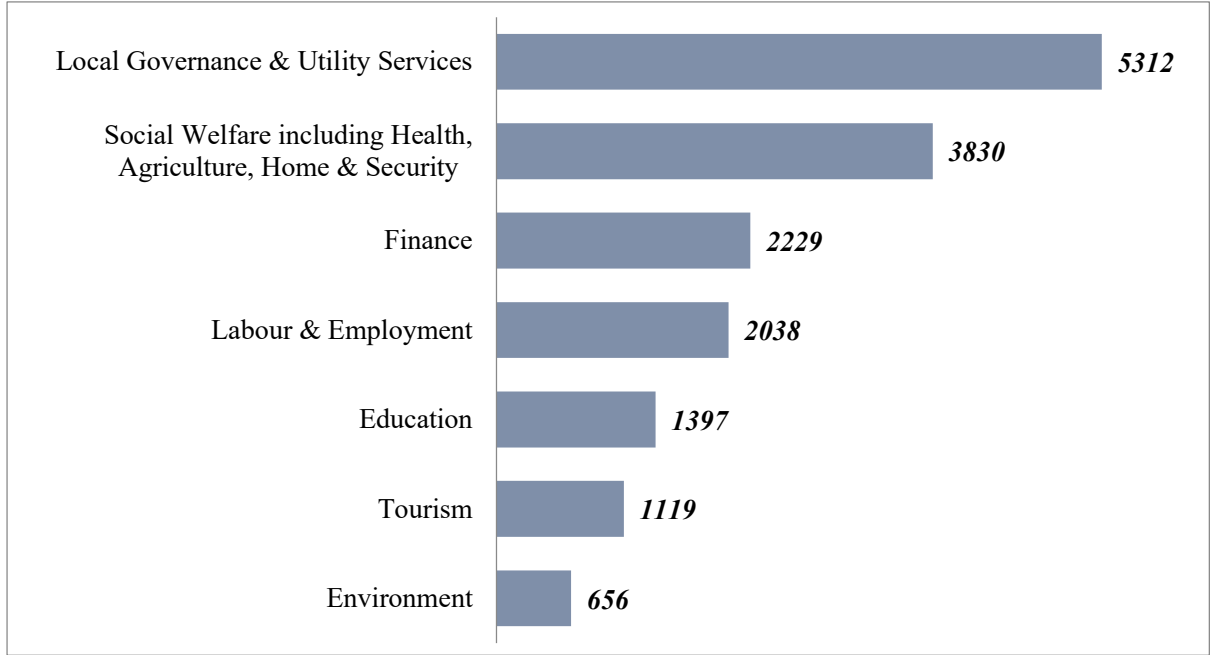
नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



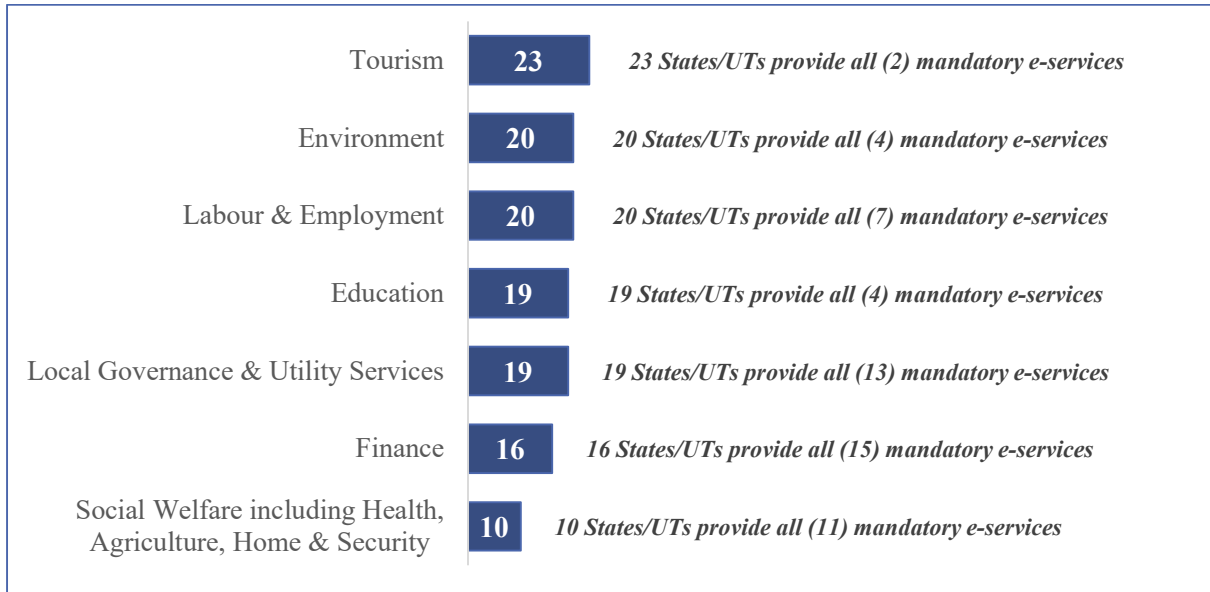
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की स्थिति की मासिक प्रगति **अनुलग्नक 8.1 में संलग्न है।**

नोट: उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 03/06/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की क्षेत्र-वार समेकित स्थिति

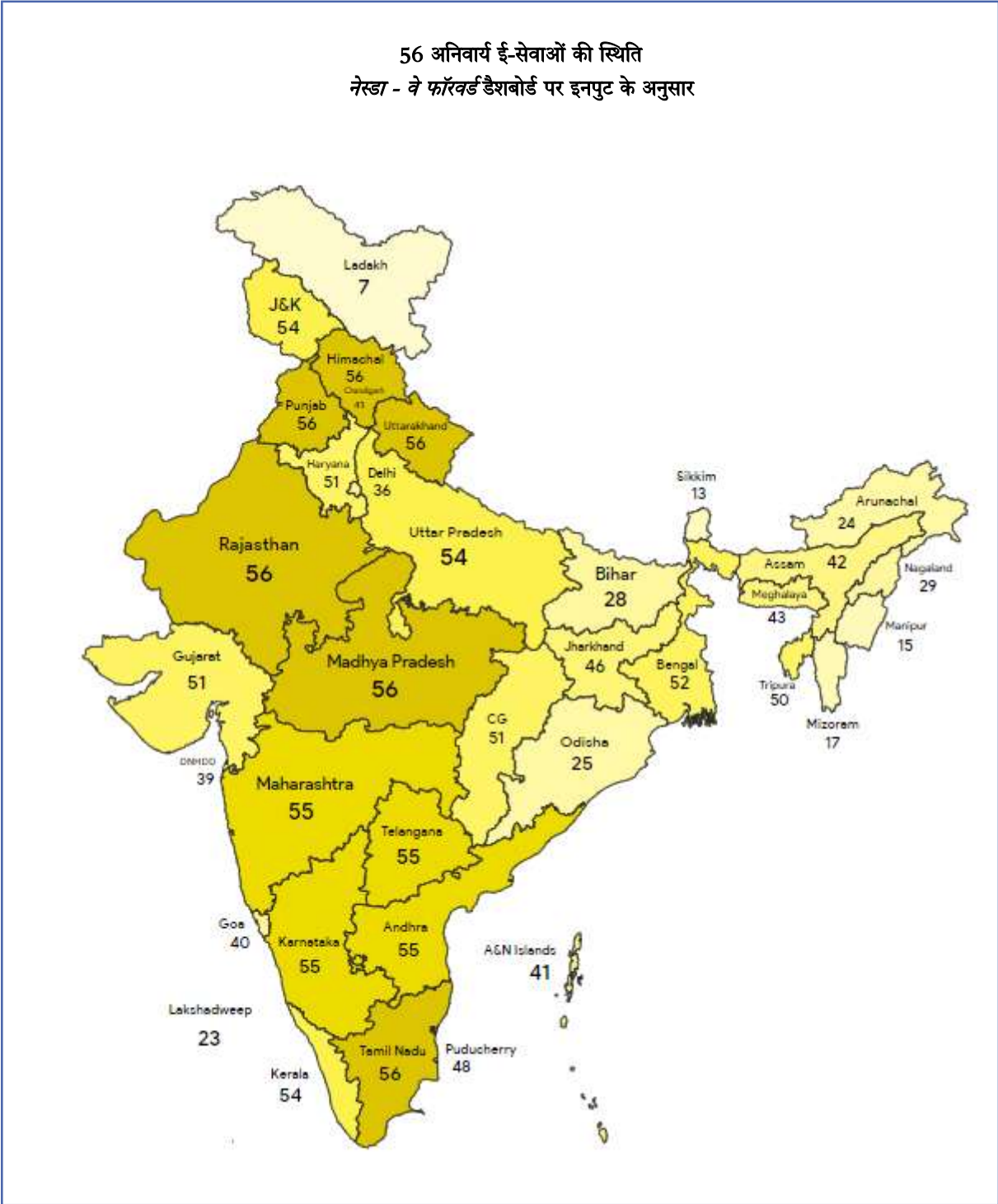


राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य ई-सेवाओं की क्षेत्र-वार परिपूर्णता स्थिति



नोट: उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 03/06/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

56 अनिवार्य ई-सेवाओं की स्थिति
नेस्डा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार

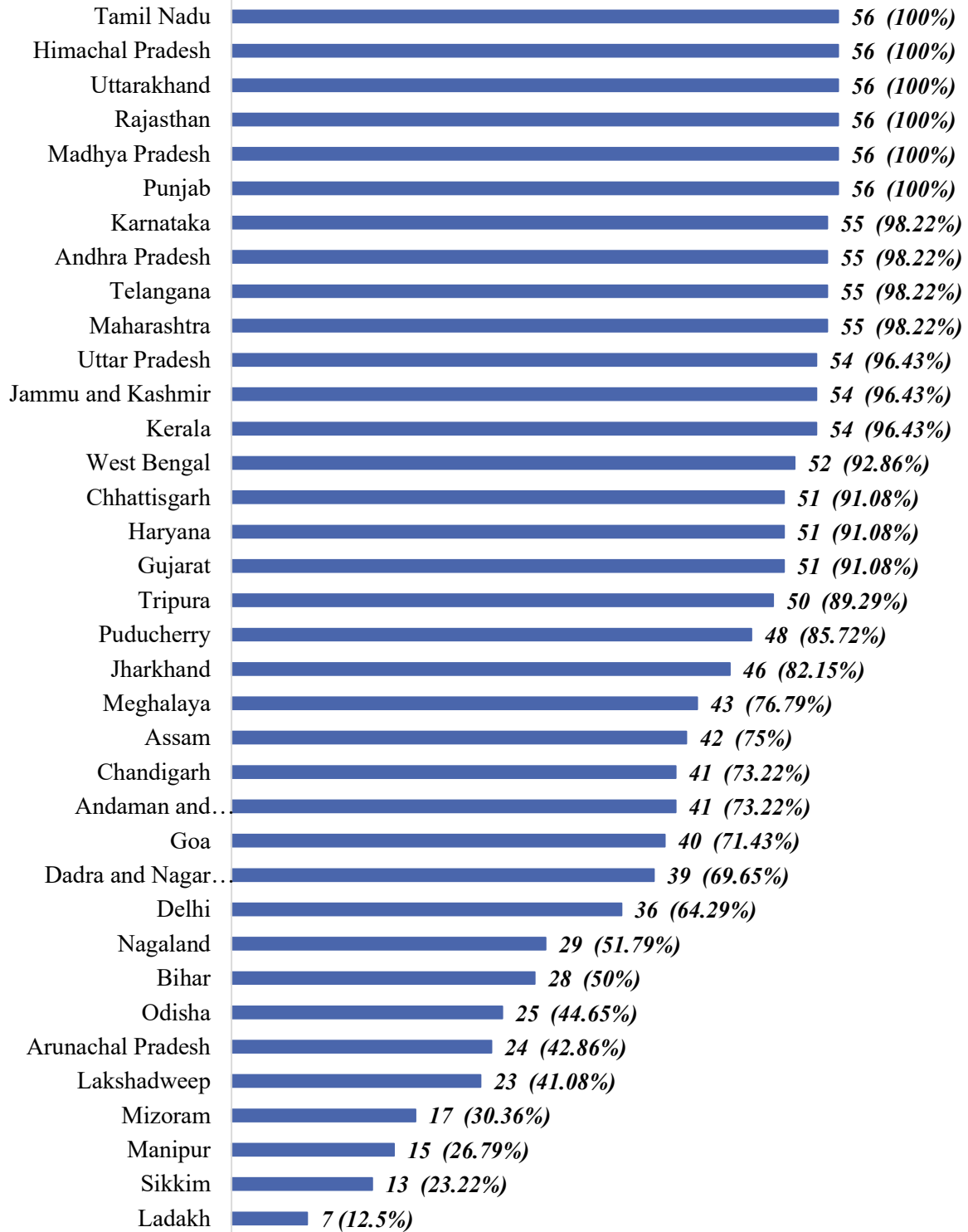


अनिवार्य ई-सेवाएँ
1,530

नोट: उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 03/06/2024 तक अपलोड किए गए हैं।



56 अनिवार्य ई-सेवाओं की स्थिति
नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर इनपुट के अनुसार



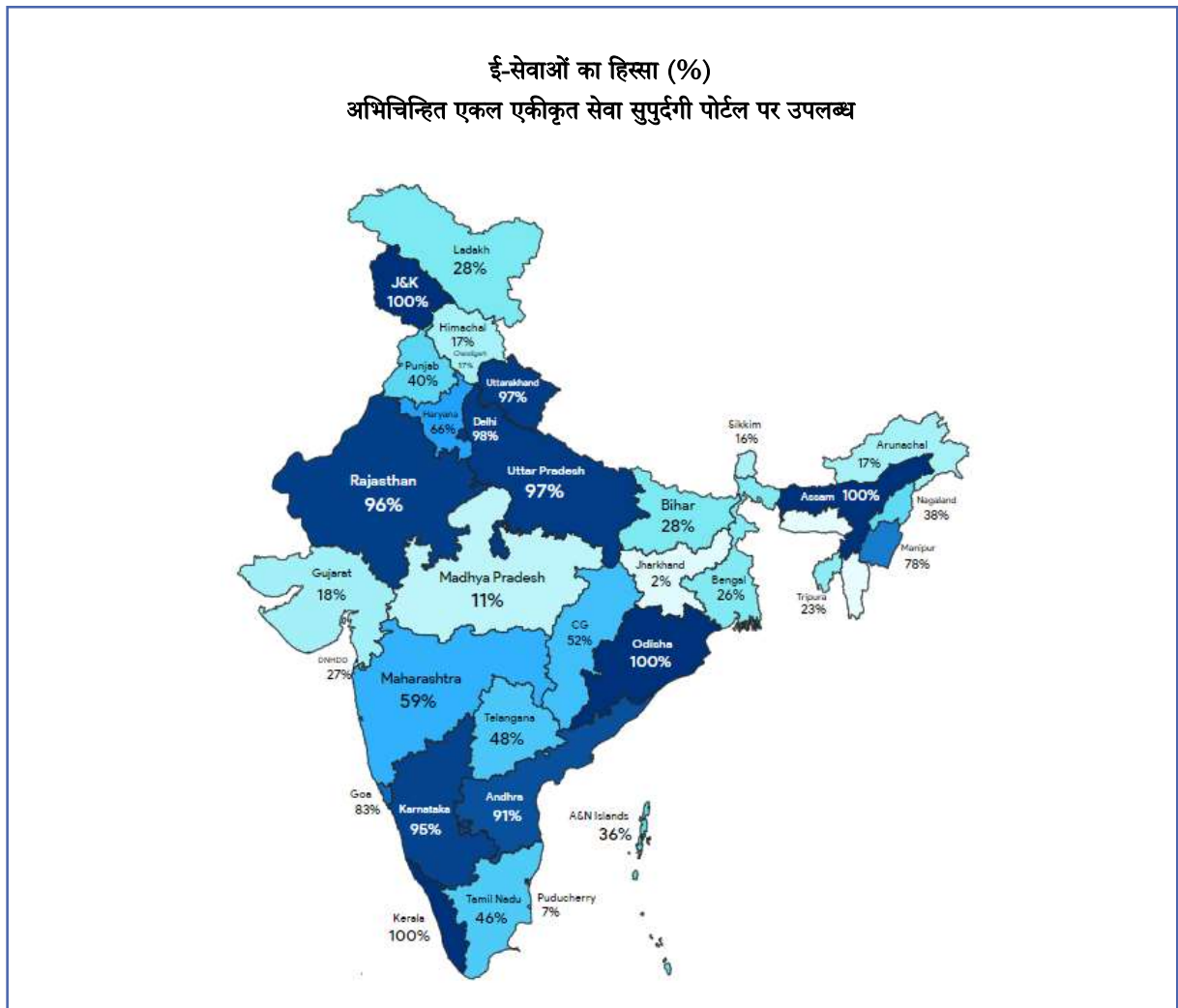
नोट: उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 03/06/2024 तक अपलोड किए गए हैं।

4. एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल

4.1. परिपूर्णता स्थिति

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकल एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल के माध्यम से ई-सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से अपनी ई-सेवा सुपुर्दगी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करता है।

एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कई विभागों से सभी सरकारी सेवाओं को एकीकृत करता है, जिससे नागरिकों को वाइड रेंज ऑफ सर्विस के लिए सिंगल पॉइंट ऐक्सेस मिलता है। उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस पर सेवाओं को समेकित करके, नागरिक कई विभागीय वेबसाइटों / फिजिकल ऑफिस के माध्यम से नेविगेट किए बिना आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे अक्सर प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण, सिंगल साइन ऑन, ऑनलाइन भुगतान गेटवे आदि जैसी सुविधाओं को शामिल करते हैं।



राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिचिन्हित सिंगल एकीकृत पोर्टल	यूआरएल	सिंगल एकीकृत पोर्टल पर ई-सेवा % (गणना)
जम्मू और कश्मीर	ई-उन्नत	eunnat.jk.gov.in	100% (1140)
केरल	ई-सेवनम	services.kerala.gov.in	100% (911)
असम	सेवा सेतु	sewasetu.assam.gov.in	100% (469)
ओडिशा	ओडिशा वन	odishaone.gov.in	100% (404)
दिल्ली	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.delhi.gov.in	98% (426)
उत्तराखंड	अपणि सरकार	eservices.uk.gov.in	97% (863)
उत्तर प्रदेश	निवेश मित्रा एवं ई-डिस्ट्रिक्ट	niveshmitra.up.nic.in एवं edistrict.up.gov.in	97% (774)
राजस्थान	ई-मित्रा	emitra.rajasthan.gov.in	96% (546)
कर्नाटक	सेवा सिंधु	sevasindhu.karnataka.gov.in	95% (721)
आंध्र प्रदेश	एपी सेवा	vswsonline.ap.gov.in	91% (524)
गोवा	गोवा ऑनलाइन	govaonline.gov.in	83% (199)
मणिपुर	ई-डिस्ट्रिक्ट	eservicesmanipur.gov.in	78% (31)
हरियाणा	सरल हरियाणा	saralharyana.gov.in	66% (503)
महाराष्ट्र	आपले सरकार	aaplesarkar.mahaonline.gov.in	59% (315)
छत्तीसगढ़	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.cgstate.gov.in	52% (149)
तेलंगाना	मीसेवा	ts.meeseva.telangana.gov.in	48% (365)
तमिलनाडु	ई-सेवई	tnesevai.tn.gov.in	46% (524)
पंजाब	कनेक्ट पंजाब	connect.punjab.gov.in	40% (196)
नागालैंड	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.nagaland.gov.in	38% (24)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.andaman.gov.in	36% (114)
लद्दाख	ई-सेवा	eseva.ladakh.gov.in	28% (13)
बिहार	आरटीपीएस बिहार	serviceonline.bihar.gov.in	28% (66)
डीएनएचडीडी	सिंगल विंडो पोर्टल	swp.dddgov.in	27% (21)
पश्चिम बंगाल	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.wb.gov.in	26% (105)
त्रिपुरा	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.tripura.gov.in	23% (60)
गुजरात	डिजिटल गुजरात	digitalgujrat.gov.in	18% (81)
चंडीगढ़	सर्विस प्लस	serviceonline.gov.in	17% (39)
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल ई-सेवा	eservice.arunachal.gov.in	17% (53)
हिमाचल प्रदेश	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.hp.gov.in	17% (83)
सिक्किम	सिक्किम एसएसओ	sso.sikkim.gov.in	16% (8)
मध्य प्रदेश	एमपी ऑनलाइन	mponline.gov.in	11% (109)
पुदुचेरी	ई-डिस्ट्रिक्ट	edistrict.py.gov.in	7% (44)
झारखंड	झारसेवा	jharsewa.jharkhand.gov.in	2% (8)
मेघालय	मेघालय ऑनलाइन	meghalayaonline.gov.in	-

नोट: एकल एकीकृत पोर्टल का उपरोक्त विवरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर 03/06/2024 तक सूचित और अपलोड किए गए हैं। लक्षद्वीप और मिजोरम में एक भी एकल एकीकृत सेवा पोर्टल नहीं है। जिन राज्यों ने नेस्टा - वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर अपने एकल एकीकृत सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाओं का URL अपलोड नहीं किया है, उन्हें (-) चिह्नित किया गया है।

4.2. सर्वोत्तम परिपाटियाँ- एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल

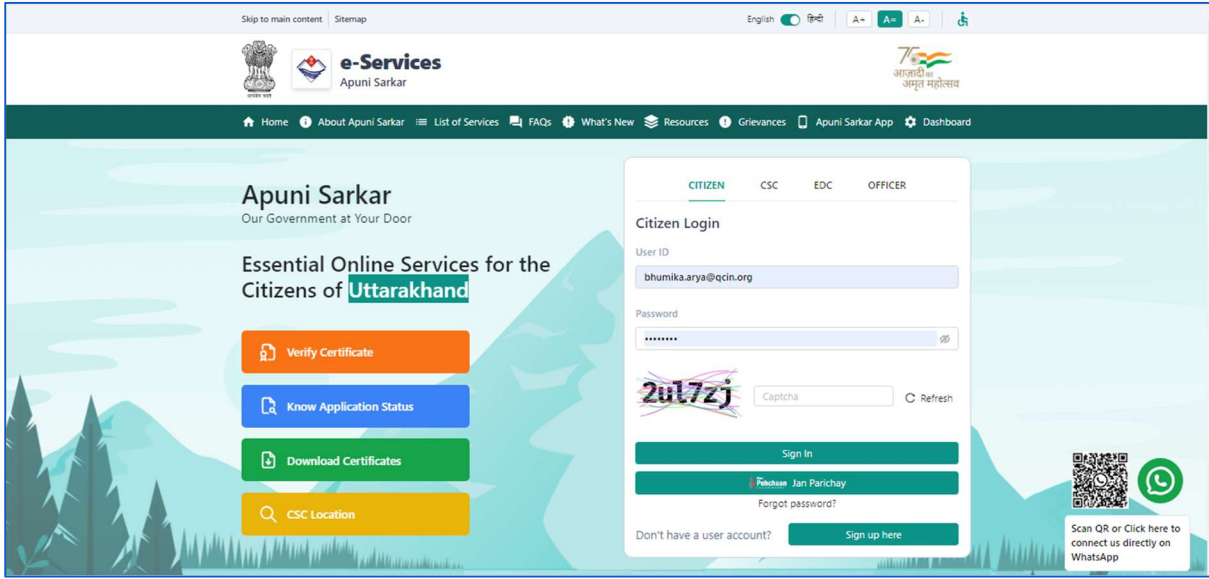
नागरिक सेवा सुपुर्दगी के लिए पोर्टलों के एकीकरण की दिशा में एक प्रवृत्ति देखी गई है क्योंकि कई नैशनैलिटीज और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सेवा सुपुर्दगी के लिए एकीकृत पोर्टल विकसित किए गए हैं। ये प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए एक एकीकृत ऐक्सेस पॉइंट प्रदान करते हैं और नेस्टा द्वारा प्रोत्साहित की जाने वाली सर्वोत्तम परिपाटियों में निहित हैं। विभिन्न विभागों या न्यायक्षेत्रों में सेवाओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करके, वे बेहतर शासन और सेवा उपलब्धता प्रदान करते हैं। ये यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि सभी नागरिक अधिकार पोर्टेबल हैं और क्लाउड पर उपलब्ध हैं। इनमें से कई पोर्टलों ने राष्ट्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इज ऑफ इंडिंग बिजनेस में वृद्धि के लिए सेवाओं को डिजिटल रूप से भी बदल दिया है और निर्णय समर्थन और विकास गतिविधियों के लिए स्थापित और उभरती हुई विभिन्न प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया है।

सेवाओं की एकीकृत और निर्बाध सुपुर्दगी नेस्टा ढांचे का एक मुख्य सिद्धांत है और ऐसे पोर्टलों को सुदृढ़ करने से नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण बढ़ेगा। एकीकृत सेवा सुपुर्दगी में सर्वोत्तम परिपाटियों के लिए इस खंड में जिन कुछ पोर्टलों और डिजिटल पहलों पर प्रकाश डाला गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पहल का नाम
1	उत्तराखंड	ई-सेवा अपणि सरकार
2	सिक्किम	सिंगल साइन ऑन
3	आंध्र प्रदेश	एपी सेवा पोर्टल



4.2.1. उत्तराखंड (ई-सेवाएं अपणि सरकार)



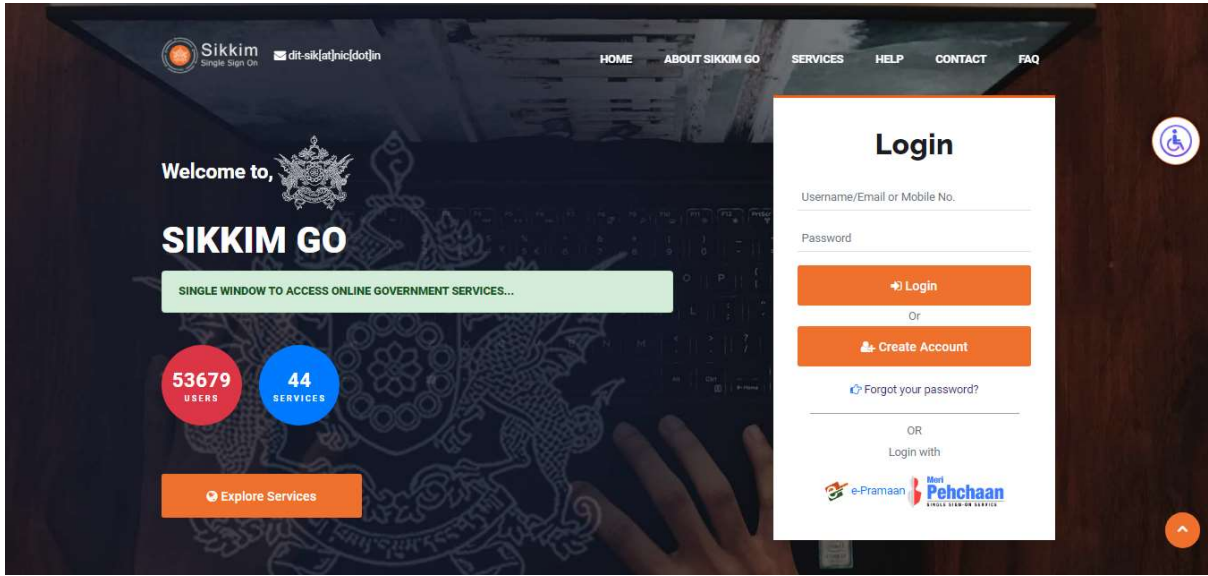
<https://eservices.uk.gov.in/>

उत्तराखंड एकीकृत सेवा सुपर्दगी पोर्टल, " अपणि सरकार", उत्तराखंड सरकार द्वारा नागरिक-अभिमुख सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करने के लिए विकसित एक अभिनव ऑनलाइन प्लैटफॉर्म है।

Key Features

- ✓ आसान पहुंच और सत्यापन के लिए, ई-पहचान और जन परिचय के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया गया।
- ✓ एकल सुरक्षित लॉगिन प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अनुकूलित डैशबोर्ड के साथ नागरिकों, पीएफसी, सीएससी और अधिकारियों को एक्सेस प्रदान करता है।
- ✓ आसान नेविगेशन और पहुंच के लिए विस्तृत जानकारी के साथ ई-सेवाओं का विभागवार वर्गीकरण।
- ✓ आवेदन आईडी का उपयोग करके आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना और पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन।
- ✓ आवेदन की स्थिति की रियल टाइम ट्रैकिंग और निगरानी प्रदान करने वाले व्यापक डैशबोर्ड।
- ✓ ऑन द गो एक्सेस के लिए अपणि सरकार मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक।
- ✓ एडजस्टेबल स्क्रीन फ्रॉन्ट आकार और कंट्रास्ट के साथ डब्ल्यू3सी अनुरूप, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है।
- ✓ आसानी से सुलभ संपर्क विवरण, हेल्पलाइन नंबर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और नए पोर्टल फीचर्स पर अपडेट।
- ✓ फ़ायरफ़ॉक्स (v90+), गूगल क्रोम (v84+), और सफारी (v14+) सहित प्रमुख ब्राउज़रों का सपोर्ट
- ✓ 98% औसत प्रोसेसिंग रेट के साथ 34 लाख से अधिक एप्लीकेशन प्रोसेस्ड किए गए, जिससे कुशल और संपर्क रहित (फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस) सेवा सुपर्दगी सुनिश्चित हुआ।

4.2.2. सिक्किम (सिंगल साइन ऑन)



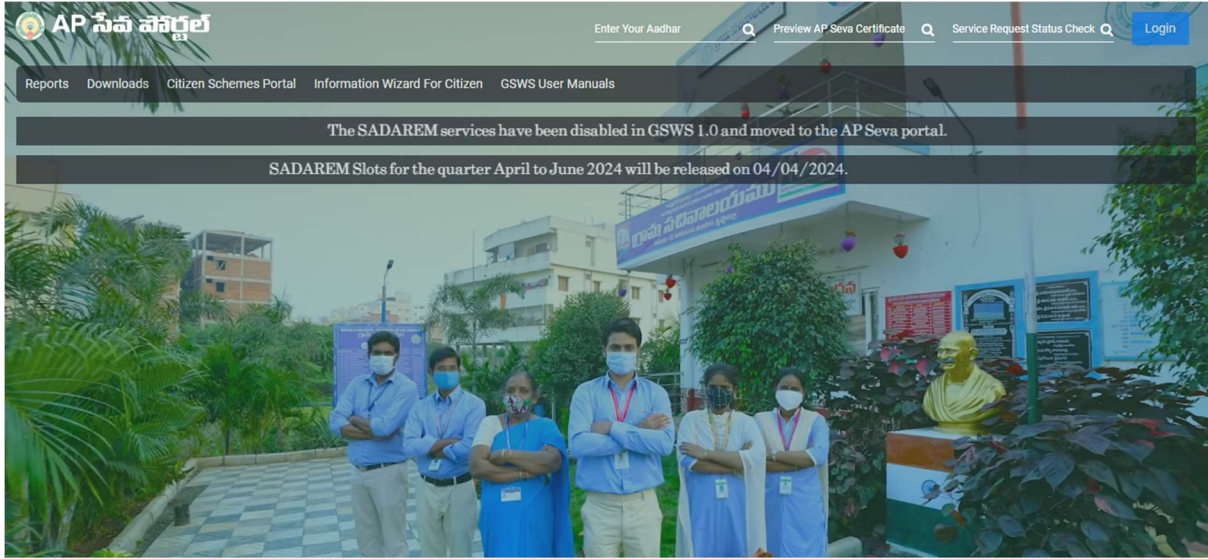
<https://sso.sikkim.gov.in/>

सिक्किम सरकार ने "सिक्किम गो" विकसित किया है, जो एक एकीकृत ऑनलाइन सेवा सुपुर्दगी पोर्टल है जो एकल साइन-ऑन प्रणाली के माध्यम से पहचान और एक्सेस मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करता है। यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म नागरिकों को एक ही क्रेडेंशियल के साथ एक बार प्रमाणित करने की सुविधा देता है ताकि वे कई राज्य-प्रदत्त अनुप्रयोगों और वेबसाइटों को देख सकें। सिक्किम गो के साथ, उपयोगकर्ता केवल एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके विभिन्न विभागों से एकीकृत सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का आसानी से लाभ उठा सकते हैं, जिससे सिक्किम के निवासियों की दक्षता और उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि हुई है।

Key Features

- ✓ एकीकृत पहचान सत्यापन और निर्बाध पहुंच के लिए मेरी पहचान और ई-प्रमाण प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत
- ✓ 15 विभागों में सभी 44 सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक लॉगिन, जिससे उपयोगकर्ता की सुविधा और सुरक्षा बढ़ेगी
- ✓ आसान पहुंच के लिए विस्तृत जानकारी के साथ ई-सेवाओं का विभागवार वर्गीकरण
- ✓ सेवा की गुणवत्ता और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोगकर्ताओं को फीडबैक देने का प्रावधान
- ✓ किसी भी शिकायत और सामान्य प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए समर्पित संपर्क जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उपयोगकर्ता मैनुअल उपलब्ध हैं
- ✓ बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और पहुंच के लिए ऐडजस्टेबल स्क्रीन फ्रॉन्ट आकार और कंट्रास्ट
- ✓ पोर्टल डब्ल्यू3सी मानकों के अनुरूप है, जो संगतता और पहुंच सुनिश्चित करता है
- ✓ यूजर इंगेजमेंट की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए वेबसाइट विज़िटर की संख्या प्रदान करता है
- ✓ 53,683 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, जो इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने और प्रभावशीलता को दर्शाता है
- ✓ ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं के साथ सुरक्षित लॉगिन, जो उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है

4.2.3. आंध्र प्रदेश (एपी सेवा पोर्टल)



<https://vswsonline.ap.gov.in/>

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विकसित एपी सेवा पोर्टल, निवासियों के घरों तक सीधे सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक सर्विस ऐक्सेस में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, यह पोर्टल विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदनों को सुव्यवस्थित करता है, पारदर्शिता बढ़ाते हुए समय और लागत की बचत सुनिश्चित करता है।

Key Features

- ✓ सुव्यवस्थित पहुँच और प्रबंधन के लिए नागरिकों और प्रशासकों के लिए समर्पित लॉगिन और डैशबोर्ड
- ✓ बेहतर अनुभव के लिए विस्तृत जानकारी के साथ शीर्ष 10 सेवाओं तक त्वरित पहुँच
- ✓ रियल टाइम निगरानी और निर्णय लेने के लिए व्यापक विश्लेषण डैशबोर्ड
- ✓ निर्बाध और कुशल सेवा सुपुर्दगी अनुभव के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड
- ✓ नागरिक शिकायतों निवारण करने के लिए एकीकृत शिकायत डैशबोर्ड
- ✓ 27 जनवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया, एपी सेवा पोर्टल 2.0, पारदर्शी रूप से बेहतर सरकारी सेवाएँ प्रदान करता है
- ✓ राजस्व और भूमि प्रशासन के लिए 30 सेवाएँ, नगरपालिका प्रशासन के लिए 25 सेवाएँ, नागरिक आपूर्ति के लिए 6 सेवाएँ, ग्रामीण विकास के लिए 3 सेवाएँ और ऊर्जा विभाग के लिए 53 सेवाएँ प्रदान करता है
- ✓ भुगतान सेवाओं को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने के लिए सक्षम भुगतान गेटवे
- ✓ दूरदराज के ग्रामीणों को उनके द्वार पर आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा

5. पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा सुपुर्दगी को मजबूत करना

नेस्टा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य, भारत की ई-गवर्नेंस प्रगति का विश्लेषण करना, ई-सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा देना और केंद्रीकृत सेवा प्लेटफार्मों का उपयोग करना है। नेस्टा के अनुरूप, डीएआरपीजी पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा सुपुर्दगी की स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिससे उनके समग्र नेस्टा स्कोर में वृद्धि हो सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्य, अपने-अपने प्रमुख वन-स्टॉप पोर्टल के तहत सभी ई-सेवाओं को समेकित कर सकते हैं ताकि पहुँच में आसानी और कुशल सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य से, डीएआरपीजी ने 29 मई, 2024 को त्रिपुरा सरकार के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें ऑनलाइन सेवा सुपुर्दगी को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यनीतियों पर चर्चा की गई, जिसमें निम्नलिखित उभरती हुई ई-गवर्नेंस पहलों पर प्रकाश डाला गया।

त्रिपुरा सरकार ने अपने ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य की प्रमुख पहलों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

त्रिपुरा "डिजिटल सेवा" नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो नागरिक-अभिमुख सेवाएँ प्रदान करता है। अक्टूबर 2022 तक, 65 हाई वॉल्यूम वाली सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिनमें स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और सर्वाइवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना शामिल है। ये सेवाएँ डिजिटल हस्ताक्षर, एसएमएस और ईमेल गेटवे, भुगतान गेटवे और सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर), उमंग, डिजिलॉकर और आरएएस (रैपिड असेसमेंट सिस्टम) जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत हैं। राज्य, निकट भविष्य में और भी अधिक सेवाओं को शुरू करने की योजना बना रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना ई-ऑफिस का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में सरलीकृत, उत्तरदायी और पारदर्शी कार्य वातावरण बनाना है। 10 जुलाई, 2024 तक, पूरे त्रिपुरा के 103 विभागों, निदेशालयों, कार्यालयों और वैधानिक निकायों में ई-ऑफिस लागू किया जा चुका है।

स्वागत एक सिंगल विंडो पोर्टल है जिसे राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उद्यमियों को स्व-प्रमाणन के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने और औद्योगिक स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरीयों के लिए त्वरित स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति देता है। स्वागत की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

Service	Count
Number of Applications Submitted	22644
Number of Online NOC Issued	21026
Number of Investor Query Submitted	36
Number of Investor Query Responded	36

स्वागत एकल खिड़की पोर्टल

- प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ संयुक्त आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना
- आवेदन से संबंधित सभी शुल्कों का ऑनलाइन भुगतान
- प्रसंस्करण के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों को आवेदनों और शुल्कों का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण
- आवेदन की स्थिति और अनुमोदन प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग
- आवेदन की स्थिति के बारे में आवेदकों और संबंधित प्राधिकारियों को एसएमएस और ईमेल सूचनाएं
- अंतिम समय सीमा के निकट पहुंचने वाली मंजूरी के लिए स्वचालित सूचनाएं
- ऑनलाइन केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से सुव्यवस्थित निरीक्षण

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित टीआरईएसपी (त्रिपुरा ग्रामीण आर्थिक विकास और सेवा सुपुर्दगी परियोजना) के तहत एक उप-परियोजना उन्नति का उद्देश्य, त्रिपुरा में ई-सेवा सुपुर्दगी को एकीकृत करना है। यह डेटाबेस को एकीकृत करके और बहुभाषी, मोबाइल-आधारित इंटरफेस का समर्थन करके अलग-अलग सेवा प्लेटफॉर्म को देखता है। आधार-सीडेड राशन कार्ड डेटाबेस का उपयोग करके, यह नागरिक प्रोफाइल के आधार पर सेवाओं की सिफारिश करता है, स्वचालित सेवा सुपुर्दगी की सुविधा देता है और शिकायत निवारण को बढ़ाता है। यह परियोजना त्रिपुरा गारंटीकृत नागरिक सेवा सुपुर्दगी अधिनियम 2020 को लागू करती है, जिसमें शुरू में 30 उच्च-संख्या वाली सेवाओं और 75 योजनाओं को एकीकृत किया जाता है। दो चरण की कार्यान्वयन योजना में शामिल हैं: समाधान अध्ययन और सिफारिश, उसके बाद प्लेटफॉर्म विकास और रोलआउट।



29 मई 2024 को त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीएआरपीजी की बैठक

ये पहल ई-गवर्नेंस परिदृश्य को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को अपनाकर नागरिक अनुभव में सुधार लाने के लिए त्रिपुरा सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

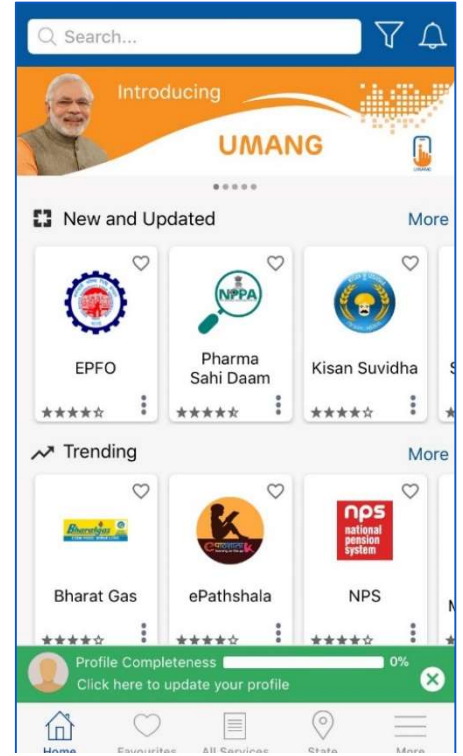
डीएआरपीजी और त्रिपुरा सरकार के बीच बैठक इस बात पर संपन्न हुई कि डीएआरपीजी ने राज्य के ई-सेवा सुपुर्दगी की स्थिति सुधारने के लिए समर्थन देगा। डीएआरपीजी और त्रिपुरा के बीच इस सहयोग से ई-गवर्नेंस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार हुआ है।

चर्चा से प्राप्त सुझावों के अनुसार, त्रिपुरा राज्य अनिवार्य ई-सेवाओं के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दे सकता है। इसके बाद अन्य ई-सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे अंततः सभी ई-सेवाओं को उनके एकीकृत सेवा सुपुर्दगी पोर्टल पर एकीकृत किया जा सकेगा।

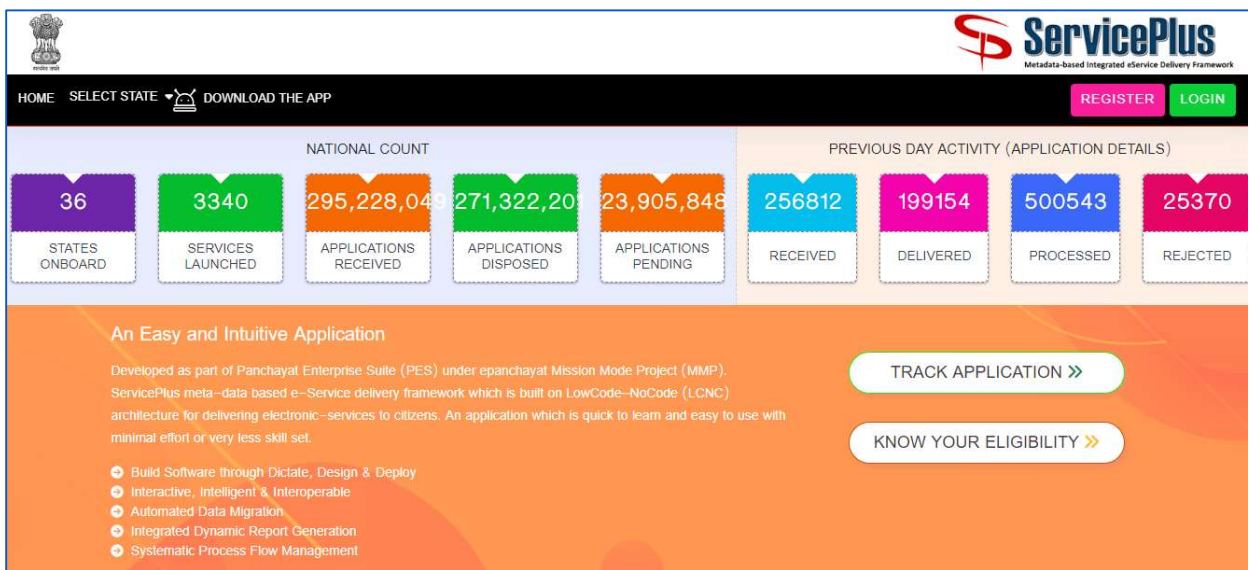
6. उन्नत ई-सेवा सुपुर्दगी के लिए डिजिटल पहल

यह द्वि-मासिक नेस्टा वे फॉरवर्ड रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) द्वारा प्रदान की जाने वाली दो केंद्रीय सरकारी डिजिटल अवसंरचना सेवाओं उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) और सर्विस प्लस पर एक नया स्पॉटलाइट शामिल करती है: ये प्लेटफॉर्म राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अपनी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण फैसिलिटेटर्स के रूप में काम करते हैं, जिससे उनके ई-गवर्नेंस परिदृश्य में वृद्धि होती है।

यह समावेशन, पूरे देश में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में ई-सेवा सुपुर्दगी के इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए विभाग के निरंतर प्रयास के अनुरूप है। उमंग और सर्विस प्लस को प्रदर्शित करके, रिपोर्ट का उद्देश्य, मजबूत डिजिटल टूल के रूप में उनकी क्षमता को बढ़ावा देना है जिसका लाभ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, अपनी ऑनलाइन सर्विस ऑफरिंग्स का विस्तार करने और नागरिकों तक इनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठा सकते हैं। हम आगे आने वाले निम्नलिखित खंडों में इन पहलों पर गहराई से चर्चा करेंगे।



UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance)



सर्विस प्लस – मेटाडेटा आधारित एकीकृत ई-सेवा सुपुर्दगी ढांचा

6.1 सर्विस प्लस

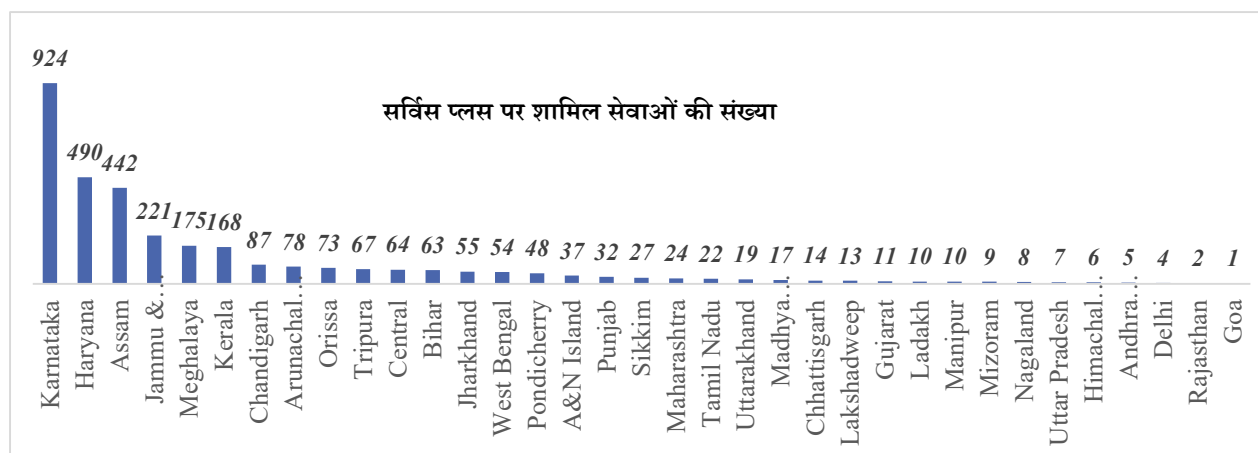
सर्विस प्लस, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है। यह एक 'लो कोड नो कोड' फ्रेमवर्क है जिसे एक सामान्य, कॉन्फिगर करने योग्य, एकीकृत, मेटाडेटा-आधारित ओपन-सोर्स मल्टी-टेनेंसी फ्रेमवर्क का उपयोग करके किसी सेवा को ई-सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसका उपयोग प्रत्येक किरायेदार (विभाग या स्थानीय सरकार) द्वारा अपनी सेवाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कॉन्फिगर करने और उच्चतम स्तर की स्केलेबिलिटी, विश्वसनीयता और अनुकूलता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सहज, कोड-मुक्त कॉन्फिगरेशन उपकरण
- अनुकूलित सेवा सुपुर्दगी अनुकूलन
- लो कोड-नो कोड सोल्यूशन फॉर ईजी डेवलपमेंट
- विविध विभागीय आवश्यकताओं के लिए बहुमुखी समाधान
- सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक कार्यात्मकताओं का एकीकरण।
- डेटाबेस और बुनियादी ढांचे का निर्बाध प्रबंधन
- रेस्ट एपीआई के माध्यम से थर्ड पार्टी एकीकरण समर्थन
- दक्षता के लिए ओपन-सोर्स फ्रेमवर्क पर निर्मित
- उन्नत कार्यक्षमता के लिए बाह्य उपकरणों का उपयोग
- अपाचे टॉमकैट के साथ विश्वसनीय अनुप्रयोग सर्वर
- स्प्रिंग और हाइब्रिड द्वारा संचालित अनुकूल फ्रेमवर्क
- केरी और बूटस्ट्रैप के साथ आधुनिक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस
- रेड हैट एंटरप्राइज लीनक्स पर सुरक्षित ऑपरेटिंग वातावरण
- विभिन्न थर्ड पार्टी समाधानों के साथ सहज एकीकरण
- पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ मजबूत डेटाबेस प्रबंधन

90% से अधिक आवेदन इन 5 राज्यों से प्राप्त होते हैं

#	राज्य	प्राप्त आवेदन (%)
1	बिहार	45.0%
2	कर्नाटक	14.7%
3	झारखंड	12.0%
4	हरियाणा	10.8%
5	ओडिशा	8.4%

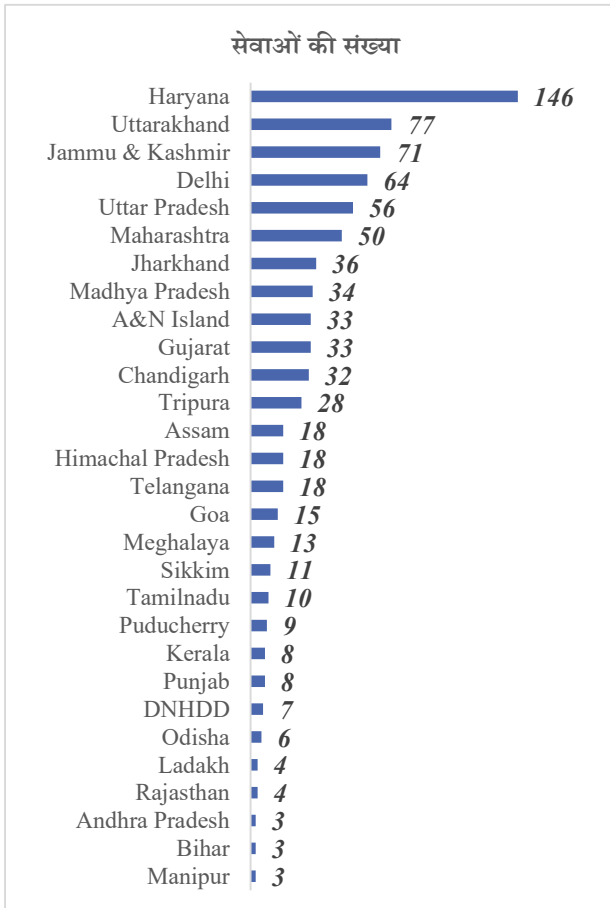


6.2 उमंग

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) को, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) द्वारा भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। उमंग, सभी भारतीय नागरिकों को मोबाइल एप्लीकेशन (आईओएस, एंड्रॉइड), चैटबॉट, वॉयस बॉट और वेबसाइट जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक एकल मंच प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

सेवाएं	दस्तावेज	इंगेजमेंट्स	ट्रांजैक्शन
<ul style="list-style-type: none"> ●केंद्रीय ●राज्य ●उपयोगिता बिल 	<ul style="list-style-type: none"> ●आधार ●ड्राइविंग लाइसेंस ●पैन ●वाहन आर.सी. ●डिजिलॉकर से भिन्न 	<ul style="list-style-type: none"> ●प्रतिक्रिया/रेटिंग ●सूचनाएं ●ग्राहक सेवा ●लाइव चैट ●चैटबॉट ●वॉयस बॉट 	<ul style="list-style-type: none"> ●स्थिति ●बिल्स ●एप्लीकेशंस ●अन्य



70% उपयोगकर्ता निम्नलिखित 10 राज्यों से हैं:

राज्य	उपयोगकर्ता %
महाराष्ट्र	14.2
उत्तर प्रदेश	12.8
तमिलनाडु	7.0
कर्नाटक	6.5
गुजरात	6.3
बिहार	5.5
पश्चिम बंगाल	5.3
राजस्थान	4.7
दिल्ली	4.5
आंध्र प्रदेश	4.3

7. सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता में सुधार

डिजिटल गवर्नेंस में नवीनतम प्रगति को दर्शाने और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, नेस्टा ढांचे का विस्तार करके तीन नए पैरामीटर शामिल किए गए हैं: **ओपन गवर्नमेंट डेटा, ई-भागीदारी** और **उभरती हुई तकनीकों का लाभ उठाना**। पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और सरकार की नई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ये तत्व महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन मापदंडों को अपने संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल में एकीकृत करें।

1. **ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी):** नियामक ढांचे के अनुरूप सरकार के स्वामित्व वाले साझा करने योग्य डेटा और इसके उपयोग की जानकारी तक सक्रिय पहुंच

- एक समर्पित ओ.जी.डी. पोर्टल या ओ.जी.डी. प्लेटफॉर्म (data.gov.in) पर प्रकाशित डेटासेट
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ओजीडी प्लेटफॉर्म लिंक का एकीकरण
- डेटा से संबंधित पहलों की देखरेख करने वाले मुख्य डेटा अधिकारी की नियुक्ति
- नेस्टा 2023 के कम से कम चार क्षेत्रों के हाइलाइट किए गए और सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटासेट
- जीआईएस मानचित्र और भूस्थानिक डेटा डाउनलोड करने का प्रावधान
- जनता को नए डेटासेट के लिए अनुरोध करने की अनुमति देना
- ओजीडी पोर्टल के उपयोग पर ट्यूटोरियल, मार्गदर्शन सामग्री और वीडियो की उपलब्धता
- ओजीडी पोर्टल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर डेवलपर कम्युनिटी को शामिल करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रलेखन

2. **ई-भागीदारी:** नीतियों और सेवाओं को साथ मिलकर डिजाइन करने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु *आईसीटी* के माध्यम से सरकारों और नागरिकों के बीच बातचीत

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ई-भागीदारी नीति प्रकाशित की गई
- माईगव पोर्टल में एक समर्पित ई-भागीदारी पोर्टल या उप-साइट की स्थापना
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल के होमपेज पर ई-भागीदारी पोर्टल लिंक का एकीकरण
- ई-भागीदारी पोर्टल के होमपेज पर सभी आगामी ई-भागीदारी और ई-परामर्श गतिविधियों के कैलेंडर और परिणामों को शामिल करना
- पोर्टल के उपयोग पर ट्यूटोरियल, मार्गदर्शन सामग्री और वीडियो की उपस्थिति
- ई-भागीदारी पोर्टल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर ई-भागीदारी और ई-परामर्श पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का प्रलेखन

3. **उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना:** डिजिटल सरकार के विकास और उन्नत सेवा सुपुर्दगी के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को रणनीतिक रूप से अपनाना

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पोर्टल पर *एआई और ब्लॉकचेन, आईओटी, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी* या *5जी* जैसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट /दृष्टिकोण की उपस्थिति
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर एआई-आधारित सेवा चैटबॉट (अंग्रेजी और स्थानीय भाषा) का प्रावधान
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल पर सेवा सुपुर्दगी में अपनाई गई किसी भी अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रलेखन

तीन अतिरिक्त मापदंडों में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शक मैनुअल के लिए मार्च की नेस्टा वे फॉरवर्ड रिपोर्ट देखें।



8. परिशिष्ट

8.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-सेवाओं की स्थिति की मासिक प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल' 23	मई' 23	जून' 23	जुलाई' 23	अगस्त' 23	सितम्बर , 23	अक्टूबर , 23	नवंबर' 23	दिसम्बर , 23	जनवरी और फरवरी 2024	मार्च 24	अप्रैल और मई 2024
जम्मू और कश्मीर	474	469	469	470	1028	1034	1075	1097	1117	1119	1119	1140
तमिलनाडु	446	445	445	445	446	446	446	1078	1101	1128	1128	1128
मध्य प्रदेश	637	731	948	1000	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
केरल	885	886	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911
उत्तराखण्ड	596	595	595	725	782	826	831	865	865	865	865	887
उत्तर प्रदेश	709	706	713	714	714	714	798	798	798	798	798	798
तेलंगाना	493	491	582	757	768	768	768	768	768	768	768	768
हरियाणा	762	757	757	757	757	755	757	757	757	757	757	757
कर्नाटक	779	747	752	752	752	752	752	755	755	755	755	755
पुदुचेरी	239	239	239	239	246	247	247	325	605	605	605	605
ओडिशा	606	574	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
राजस्थान	248	248	248	525	536	547	549	549	549	549	566	566
महाराष्ट्र	150	148	337	441	521	533	533	533	533	533	534	534
हिमाचल प्रदेश	500	494	500	500	500	500	500	500	500	501	502	503
पंजाब	486	483	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
असम	263	259	259	259	259	452	469	469	469	469	469	469
गुजरात	191	228	444	443	443	443	443	443	443	443	443	443
दिल्ली	412	416	416	436	436	436	436	436	436	436	436	436
ओडिशा	211	373	383	383	404	404	404	404	404	404	404	404
पश्चिम बंगाल	290	323	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
मेघालय	252	217	223	223	249	306	340	363	363	363	363	363
झारखण्ड	316	294	310	311	333	333	333	333	333	333	333	333
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	164	171	171	199	200	206	239	239	321	321	321	321
अरुणाचल प्रदेश	34	101	298	298	309	309	309	309	309	309	309	309
छत्तीसगढ़	272	270	284	284	284	284	287	287	287	287	287	287
त्रिपुरा	233	230	251	262	267	270	269	269	263	263	263	264
गोवा	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
बिहार	222	234	238	238	237	237	237	238	238	238	238	238
चंडीगढ़	231	221	221	224	224	224	224	224	224	224	224	224
मिजोरम	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
दादरा नगर हवेली दमन और दीव	39	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
नगालैंड	34	34	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
सिक्किम	25	25	36	36	43	51	51	51	51	51	51	51
लद्दाख	32	32	32	46	46	46	46	46	46	46	46	46
लक्षद्वीप	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	42
मणिपुर	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
कुल	11,614	11,902	13,051	13,867	14,736	15,075	15,295	16,088	16,487	16,517	16,536	16,581

किसी भी सुझाव के लिए कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें:

श्रीमती सरिता तनेजा

उप सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

5^{वां} तल, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली

संपर्क : 011- 23401457

ईमेल आईडी: sarita.taneja@nic.in





सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

भारत सरकार